मल्टीमीडिया प्रशिक्षण किट

समूह चर्चा और मामले के अध्ययन: मानव अधिकार, आईसीटी और इंटरनेट

डेविड सौतेर: द्वारा विकसित

समूह चर्चा के उपयोग के लिए प्रश्न (कार्यशाला पूर्वान्ह)

इन सवालों से प्रतिभागियों के लिए एक अवसर प्रदान करना चाहिए कि टेक्स्ट हैंड आउट और प्रस्तुति में उठाए गए मुद्दों में से कुछ का पता लगाने के लिए अनुभवों को साझा करें.

1. मेरा देश / हमारे देशों में मानव अधिकारों के लिए इंटरनेट से सबसे महत्वपूर्ण अवसरों और खतरों में क्या किया गया है? अधिकार की व्याख्या के रास्ते में क्या परिवर्तन, यदि कोई हो, की आवश्यकता होती है?
2. क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवहार हमेशा राष्ट्रीय कानूनी और अधिकारों के रूपरेखा में एक ही तरह से माना जाना चाहिए? ऑनलाइन प्रवर्तन बहुत मुश्किल या असंभव है, तो क्या करना चाहिए?
3. क्या इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए? यदि हां, तो इसमें क्या शामिल होगा और मेरे देश / हमारे देशों में इसे लागू करने के लिए क्या आवश्यकता होगी?

4. राष्ट्रीय कानून के प्रवर्तन और अधिकार के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कानूनी उपकरणों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अधिकार शासन द्वारा जिन्हे सक्षमता प्रदान की जाती है के लिए इंटरनेट का निहितार्थ क्या हैं ?
5. अधिकारों के ऑनलाइन क्रियान्वयन के संबंध में राज्य की भूमिका क्या है?

समूह चर्चा के लिए मामले के अध्ययन और उदाहरण -परिदृश्य 1

चीन में गूगल

चीन में इंटरनेट का उपयोग व्यापक लेकिन सीमाबद्ध है. चीनी नागरिकों द्वारा इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है और जनता की भागीदारी, अभिव्यक्ति और सहयोग के लिए इंटरनेट ने अभिव्यक्ति के नए माध्यम सुलभ कराये हैं. आम तौर पर इंटरनेट का उपयोग नियंत्रित किया जाता है व्यवस्था के द्वारा जिसे "चीन की महान फ़ायरवॉल" कहा जाता है, जो राजनीतिक प्रणाली की आलोचना की सामग्री के उपयोग को को छान कर प्रस्तुत करता है. चीनी इंटरनेट उद्योग के भीतर ऑनलाइन गतिविधियों जो राज्य सुरक्षा, शत्रुतापूर्ण या अन्यथा आपत्तिजनक को स्वयं सेंसरशिप की व्यवस्था से प्रतिबंधित कर दिया जाता है. फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और Blogspot सहित कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट, चीन में प्रतिबंधित हैं, और उनके स्थानीय समकक्ष राज्य द्वारा निगरानी कर रहे हैं(हालांकि कुछ उपयोगकर्ताओं प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से

उन तक पहुँच रहे हैं). खोज इंजन के माध्यम से जानकारी तक पहुंच छानने के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और खोजों में शामिल नहीं है सामग्री जो सरकार राजनीतिक रूप से अवांछनीय मानता है.

गूगल, कई देशों में 70% से अधिक की बाजार हिस्सेदारी के साथ, दुनिया का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला खोज इंजन है. यह वीडियो फ़ाइल साझा वेबसाइट यूट्यूब का मालिक भी है. जून 2006 में, चीनी सरकार के साथ बातचीत के बाद, गूगल सरकारी सेंसरशिप के अधीन परिणामों के साथ, अपनी चीन आधारित साइट google.cn का शुभारंभ किया. गूगल का तर्क है कि उसकी उपस्थिति चीन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए फायदेमंद था, अनुपस्थिति के बदले: "खोज परिणामों को हटाए जाना गूगल के मिशन के साथ असंगत है, कोई जानकारी उपलब्ध न कराना (या नहीं के बराबर कोई जानकारी कि एक भारी अपमानित उपयोगकर्ता अनुभव है) हमारे मिशन के साथ और अधिक असंगत है. गूगल का विचार उपलब्ध है :googleblog.blogspot.co.uk/2006/01/google-in - china.html. असहमत अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के कुछ कार्यकर्ताओं का तर्क है कि, गूगल भागीदार हो गया है अपने इस समझौते के कारण राज्य सेंसरशिप में.

google.cn चीन में काफी उपयोग किया जाता है, पर गंभीरता से चीनी खोज इंजन Baidu के प्रभुत्व को चुनौती नहीं दे पा रहा है. जनवरी 2010 में गूगल ने घोषणा की, कि वो शिकार हुआ है हैकिंग हमलों का, जिसमें गूगल जीमेल खाते

भी शामिल हैं, हैकिंग हमलों ने चीन में जन्म लिया है, और परिणाम के रूप में, यह चीन से वापस होगा क्योंकि यह एक बिना सेंसर खोज सुविधा प्रदान करने में असमर्थ थे.

गूगल का विचार उपलब्ध है googleblog.blogspot.co.uk/2010/01/new-approach-to-china.html.

इस उदाहरण से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है:

en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship_in_the_People%27s_Republic_of_China

- en.wikipedia.org/wiki/Google_China
- hardboiled.berkeley.edu/archived-issues/issue-13-3/google-vs-china-what-happened

चर्चा के लिए प्रश्न:

1. क्या एक इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) या इस तरह के एक खोज इंजन के रूप में ऑनलाइन सेवा प्रदाता (ओएसपी), इंटरनेट सामग्री के उपयोग के लिए निषेध , जो ऑनलाइन सेवा प्रदाता या इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा अनुचित माना जाता है या विशेष देशों में कानून या सामाजिक मानदंडों के विरोध में है?

2. क्या सेंसरशिप प्रतिबंध के बावजूद, चीन में सेवाएं प्रदान करने के लिए गूगल सही था क्योंकि उनका मानना है कि अभी भी चीनी नागरिकों के लिए सामग्री के लिए उपयोग में सुधार होगा?

3. क्या चीन की तरह है की सरकार, अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट पर सामग्री के लिए उपयोग सेंसर करने में सक्षम होंगी, या इंटरनेट की गतिशीलता लिए उनके ऐसा करने के प्रयासों को हरा देंगी?

समूह चर्चा के लिए अध्ययन और उदाहरण - परिदृश्य 2

बाल यौन शोषण इंटरनेट गवर्नेंस के विचार विमर्श में एक प्रमुख विषय रहा है. बालयौन शोषण की छवियाँ (हालांकि आमतौर पर इसे “बच्चे को अश्लील साहित्य" कहा जाता है, बाल संरक्षण एजेंसियों के लिए यह पसंदीदा शब्द नहीं है,) अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत निषिद्ध हैं.बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार शासन का हिस्सा है, में यह निहित है की सरकारों को आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि "बच्चों का अश्लील प्रदर्शन और सामग्री के माध्यम से को रोकने का प्रबंध करे ."बाल यौन शोषण छवियों इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR) के अनुच्छेद 19 द्वारा संरक्षित नहीं हैं।

सार्वजनिक नीति के संदर्भ में, यह विषय बच्चों और तस्करी की हिंसा, लोभ सहित अन्य बच्चे के संरक्षण के मुद्दों से संबंधित है. यह वयस्क अश्लील साहित्य

से एक अलग मुद्दा है जो,स्पष्ट रूप से मानव अधिकारों के शासन के भीतर संबोधित नहीं है,लेकिन कुछ सरकारें सार्वजनिक नैतिकता की अपनी व्याख्या के अनुसार इसको प्रतिबंधित करने के लिए प्रयासरत रहती हैं.

इंटरनेट हाल के वर्षों में बाल यौन शोषण छवियों के वितरण के लिए मुख्य चैनल बन गया है। अवैध चित्र और वीडियो अब विभिन्न क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्रों के पार, ऑनलाइन साझा हो रहे हैं. बाल यौन शोषण की छवियों के उत्पादन, वितरण और पहुंच का पीछा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई में वृद्धि हुई है.

बाल यौन शोषण के साथ संबंध प्रवर्तन तंत्र आम तौर पर वैध अभिव्यक्ति और एसोसिएशन को भी दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो निगरानी और सेंसरशिप तकनीक में शामिल है.मानव अधिकारों पर काम करने वाले पेशेवर इस विषयक उपलब्ध स्वतंत्रता और गोपनीयता से चिंतित होकर इस बात की वकालत करते हैं कि बाल यौन शोषण के खिलाफ उठाये जाने वाले कदमों में ज्यादा छूट नहीं दे जानी चाहिए.वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इस विषयक ISPs और OSPs पर मौजूद व्यक्तिगत डाटा के प्रयोग के लिए विशेषाधिकार का प्रयोग करने के अधिकार से भी चिंतित हैं.

विभिन्न देशों ने इस क्षेत्र में कानूनों के प्रवर्तन के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाया है.यूनाइटेड किंगडम का इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (आईडब्ल्यूएफ) एक

प्रभावशाली मॉडल बन गया है. यह एक स्व-नियामक संस्था है और ऑनलाइन बच्चे के यौन शोषण छवियों ISPs और OSPs के साझा प्रयास से इस विषय पर पर नज़र रखता है ,और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस विषय पर रिपोर्ट भी करता है और क्रियान्वित करता है " नोटिस और टेक डाउन " पद्धति जिसके तहत ISPs और ISPs को अपने सर्वर से कंटेंट हटाना पड़ता है.

इसको एक स्वतंत्र स्व-नियामक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य था इस तरह के कंटेंट को यूनाइटेड किंगडम में होस्ट करने से रोक जा सके और साथ ही साथ इंटरनेट उद्योग के खिलाफ किसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई से भी बचा जा सके,अगर इस तरह के कंटेंट को किसी ने इंटरनेट के माध्यम से UK में देख लिया तो.

हालाँकि आईडब्ल्यूएफ ने ज्यादातर अपने आप को विवाद से बचाया है,इसने कभी-कभी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रकाशन के बीच सीमा किस तरह निर्धारित की जाये इस विषयक मुद्दे उठाये हैं, उदाहरण के लिए 2008 में- कानूनी रूप से उपलब्ध एक रिकॉर्ड एल्बम के कवर को विक्कीपीडिआ द्वारा उस कवर को प्रकाशित करने से मन करके.

इस उदाहरण के बारे में जानकारी में पाई जा सकती है:

- www.iwf.org.uk

- news.bbc.co.uk/1/hi/uk/7770456.stm
- www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop
- www.article19.org/join-the-debate.php/36/view

चर्चा के लिए प्रश्न

1. वैध अभिव्यक्ति को प्रभावित किए बिना, सरकारें कैसे प्रतिकूल यौन चित्रों के माध्यम से बाल शोषण को रोकने के लिए अपने दायित्व को पूरा कर सकती हैं?

2. आई एस पी एस और OSPs का उत्तरदायित्व क्या हैं ? क्या इंटरनेट वॉच फाउंडेशन अन्य देशों के लिए एक उपयुक्त मॉडल प्रदान करता है?

3. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार शासन भी सरकारों से यह अपेक्षा रखता है के नस्लीय भेदभाव,जातीय सर्वोच्चता, जातीय घृणा और शह के अवैध प्रसार करने (नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुच्छेद 4) को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे. सरकारों वे बाल यौन शोषण की छवियों के विषय में है के रूप में इस सामग्री के बारे में उसी तरह से कार्य करना चाहिए? क्या सरकारों को इस सामग्री के बारे में उसी तरह से कार्य करना चाहिए जिस तरह वे बाल यौन शोषण की छवियों के विषय में करती हैं ?

समूह चर्चा के लिए अध्ययन और उदाहरण - परिदृश्य 3

युगांडा में ऑनलाइन गोपनीयता, अभिव्यक्ति और एलजीबीटी अधिकार

समलैंगिकता युगांडा में प्रतिबंधित है और इसके खिलाफ आक्रामक विरोध काफी व्यापक है.2009 में, देश की संसद में एक निजी सदस्य का बिल पेश किया गया था जिसके अनुसार समलैंगिकता के खिलाफ दंड को बढ़ाने का प्रावधान था और कुछ परिस्थितियों में मौत की सजा का प्रावधान भी था .इस बिल को पर्याप्त समर्थन प्राप्त था.हालांकि विधान अब तक अधिनियमित नहीं किया गया है, यह मुद्दा जनता और संसद के बीच बहस का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है , और युगांडा की सरकार पर इस विषय पर काफी अंतरराष्ट्रीय दबाव रहा है. मसौदा कानून के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन याचिका को दुनिया भर से लगभग आधे लाख लोगों के हस्ताक्षर हासिल हुए .

2009 में युगांडा के दो अखबारों में बहुत सारे लोगो के नाम प्रकाशित किये, और दावा किया कि जाहिर तौर पर ये लोग समलैंगिक थे, फलस्वरूप इस खबर ने उनके खिलाफ हिंसा भड़काने का काम किया. जनवरी 2011 में एक प्रमुख समलैंगिक कार्यकर्ता जिनकी तस्वीर इन अखबारों से एक में प्रकाशित हुई थी,की हत्या कर दी गयी थी . इस विषय पर जनवरी 2013 में युगांडा के एलजीबीटी नागरिकों के खिलाफ एक फेसबुक पेज की शुरुआत को काफी ऑनलाइन यातायात (चर्चा) और प्रचार मिला. जवाब में युगांडा के एलजीबीटी कार्यकर्ताओं द्वारा Change.org पर एक ऑनलाइन याचिका, फेसबुक को हटाने की मांग को लेकर शुरू किया गया था कि फेसबुक के पेज पर ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रकाशित होने

के कारण- जिनके बारे में ये अफवाह है कि वो समलैंगिक हैं, या वास्तव में समलैंगिक हैं - उनके खिलाफ जनाक्रोश, फायरिंग, और उनको ख़त्म करने के प्रयास शुरू किये गए है और ईसीए इस पेज को हटाया जाना चाहिए. फेसबुक ने इस याचिका के बाद सम्बद्ध पृष्ठ हटा दिया.

प्रचारकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में, युगांडा में फेसबुक का उपयोग ब्लॉक करने के लिए फेसबुक को अनुरोध किया और तर्क यह था कि फेसबुक पर इस तरह की सूचनाओं का यूगांडा के किसे भी फेसबुक पेज पर पाया जाना फेसबुक की मानव अधिकारों की प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन है.

इस उदाहरण के बारे में जानकारी में पाई जा सकती है:

- en.wikipedia.org/wiki/Uganda_Anti-Homosexuality_Bill
- news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/8542341.stm
- www.huffingtonpost.com/2013/01/07/ugandan-anti-gay-facebook-page_n_2427078.html
- www.bigeye.ug/news/1367/FACEBOOK-To-Be-Banned-From-UGANDA/#.UQEX4CevEsK

चर्चा के लिए प्रश्न

1. क्या पृष्ठ पर प्रतिबंध लगाने का फेसबुक का अधिकार सही था? ऐसा करने के लिए मानव अधिकारों के आधार क्या हैं?

2. इस उदाहरण से गोपनीयता और सुरक्षा के रूप में अभिव्यक्ति और अन्य अधिकारों की स्वतंत्रता के बीच संबंधों के बारे में क्या पता चलता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए निहितार्थ क्या हैं?

3. फेसबुक इस मुद्दे के एक परिणाम के रूप में युगांडा में अपनी साइट के लिए उपयोग ब्लॉक करने का फेसबुक का फैसला वैध था ? क्या ऐसी कोई भी परिस्थितियां हैं जिनमे फेसबुक को इस तरह के कदम उठाने चाहिए?

अंतिम चर्चा सत्र में उपयोग के लिए प्रश्न

1. इंटरनेट पर मानव अधिकारों की रक्षा करने में संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, और राष्ट्रीय सरकारों की क्या भूमिका होना चाहिए?

2. मानव अधिकारों की रक्षा और अपने काम में सुधार करने के लिए मानव अधिकार संगठन इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकते हैं?